अल्प संख्यक समुदायों के उत्थान में तेजी लाने के लिये बैंकों को दिशा निर्देश

310 **श्री मोर्जा इर्शादबेग :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 15 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत अल्पसंख्यक समुदायों के उत्थान की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिये बैंकों को क्या मार्ग निर्देश जारी किये गये हैं तथा क्या नई सरकार ने इस कार्यक्रम को लागू करने के लिये कोई निर्णय लिया है ;

(ख) कितने बैंकों में इस प्रयोजनार्थ विशेष कक्ष खोले गये हैं ; और

(ग) इस कार्यक्रम के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दंडवते) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा है कि अल्पसंख्यक समुदायों को पर्याप्त ऋण देने के लिये उपाय करें । सरकार अल्पसंख्यकों के कल्याण की योजना को जारी रखेगी । भारतीय रिजर्व बैंक के सुझाव पर बैंकों द्वारा किये गये उपायों में से कुछ निम्नलिखित है :—

(एक) प्रत्येक बैंक में एक विशिष्ट सैल खोला जाय ।

(दो) अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण देने के उपाय किये जाये और इस सबध में हुई प्रगति की समीक्षा नियमित रूप से जिला परामर्श दात्री समितियों और जिला स्तरीय बैंकर्स समितियों की बैठकों में की जायें ।

(तीन) जहां अल्प संख्यक समुदाय के लोगों की आबादी अधिक है और खासतौर से उन 40 जिलों में जिनको अल्पसंख्यक समुदाय बाहुल्य माना गया है, सरकार के निर्धनता-रोधी कार्यक्रमों का व्यापक प्रचार किया जाना चाहिए ।

(चार) पता लगाए गये 40 जिलों में से प्रत्येक में प्रायोजक बैंक को केवल अल्प संख्यक समुदाय के लोगों के लिये ऋण के प्रवाह से संबंधित समस्याओं पर निगरानी रखने के लिये एक अधिकारी रखना चाहिये । बैंक ऋणों से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों की अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों में प्रचार करने की जिम्मेदारी इस अधिकारी की होनी चाहिये और उसे इनके हितों के लिये शाखा प्रबन्धक के सहयोग से उपयुक्त योजनायें भी बनानी चाहियें ।

(पांच) इन 40 जिलों में कार्यरत प्रायोजक बैंकों को अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों के लिये उद्यमी विकास कार्यक्रम आयोजित करने चाहियें, ताकि उन्हें बैंकों द्वारा वित्त पोषित विभिन्न कार्यक्रमों से लाभ उठाने के योग्य बनाया जा सके ।

(छः) पता लगाये गये 40 जिलों और देश के सभी जिलों में तिमाही आधार पर अल्प संख्यक समुदाय के लोगों को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में ऋण की निगरानी करने के लिये भारतीय रिजर्व बैंक ने एक संशोधित प्रपत्र भी लागू किया है ।

भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों में इस उद्देश्य के लिये विशिष्ट सैल स्थापित किये जा चुके है। भारतीय रिजर्व बैंक इस संबंध में बैंकों की प्रगति की निगरानी करता है, ताकि यह सुनिश्चित कर सके कि विशिष्ट अल्प संख्यक समुदायों के कमजोर वर्ग के लोग बैंक ऋणों में अपना उचित हिस्सा प्राप्त कर सके ।

राष्ट्रीय वस्त्र निगम, गुजरात के तकनीकी एवं अधिकारी वर्ग के अधिकारियों द्वारा ज्ञापन

311. **श्री मोर्जा इर्शादबेग :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय वस्त्र निगम, गुजरात के तकनीकी एवं अधिकारी वर्ग के अधि-

कारियों के संघ द्वारा वस्त्र मंत्री जी को दिये गये ज्ञापन पर सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(ख) इस मामले के कब तक निपटाये जाने की संभावना है तथा विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्री और साथ में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) राष्ट्रीय वस्त्र निगम (एन.टी.सी.) मिलों के तकनीकी एवं अधिकारी स्टाफ संघ (गुजरात) से प्राप्त अभ्यावेदन पर विचार किया गया था । सरकार ने एन.टी.सी. के सभी सहायक निगमों मे तकनीकी और पर्यवेक्षी स्टाफ के वेतनमानों में एकरूपता लाने के प्रश्न पर विचार करने के लिये एक संयुक्त समिति गठित कर दी है । हालांकि संयुक्त समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट निकट भविष्य में ही प्रस्तुत किये जाने की संभावना है, किन्तु इसके लिये ठीक-ठीक समय-समीक्षा बता पाना संभव नही होगा कि एन.टी.सी. के सहायक निगमो के, जिसमें एन.टी.सी. (गुजरात) भी शामिल है, तकनीकी और पर्यवेक्षण संबंधी स्टाफ के वेतनमानों पर निर्णय कब तक ले लिया जायेगा ।

देश में बन्द पड़ी कपड़ा मिलें

312. **श्री मोर्जा इर्शादबेग** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा कितनी कपड़ा मिले चलायी जा रही है तथा उसमें से कितनी मिलें इस समय बन्द पड़ी हैं, तथा उन्हे पुनः आरम्भ करने के संबंध में सरकार की क्या योजना है ; और

(ख) इन मिलों के बन्द हो जाने से कितने कामगार बेकार हो गये हैं तथा उन्हें काम पर लगाने तथा उनकी मदद करने के संबंध में क्या योजनायें आरम्भ की गयी हैं तथा उसके लिये क्या समय-सीमा निर्धारित की गयी है ?

वस्त्र मंत्री और साथ में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार (श्री शरद यादव) : (क) इस समय राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अधीन 124 मिलें तथा ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन के अधीन 2 कपड़ा मिलें हैं, जो केन्द्रीय सरकार के अधीन हैं । राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अधीन 124 कपड़ा मिलों में से 2 मिलें जो 1974 में राष्ट्रीयकरण के समय बन्द हो गयी थीं, मशीनों की खराब स्थिति के कारण पुनः चालू नही की जा सकी । ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन के अन्तर्गत आने वाली सभी मिलें इस समय चालू हैं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

सरदार सरोवर परियोजना

313. **श्री मोर्जा इर्शादबेग** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरदार सरोवर परियोजना के निर्माण के संबंध में अभी तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) इस परियोजना पर अभी तक कितनी धनराशि खर्च हुई है तथा प्रयोजनार्थ किये गये वित्तीय आबंटनों का ब्यौरा क्या है ; तथा इस परियोजना के संबंध में विश्व बैंक का विचार क्या है ; और

(ग) गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र सरकारों द्वारा इस संबंध में कितनी प्रगति की गई है ?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनुभाई कोटाडिया) : (क) से (ग) लगभग 1000 करोड़ रुपये के वितरण प्रणाली सहित बांध पर मुख्य कार्य, नहर, विद्युत-गृह का निर्माण चल रहा है । 1000 करोड़ रूपये की लागत के कार्यों के लिये संविदायें देने हेतु प्रस्तुत किये गये हैं। अक्तूबर, 1989 तक 726.32 करोड़ रुपये व्यय किये गए हैं । वर्ष 1989–90 के लिये आवटन 250.10 करोड़ रूपये था । दिसम्बर, 1989 मे